(b) The Fruits and Vegetables outlets in Delhi are owned by the NDDB and its operating cost are being absorbed by the F&V Project of the NDDB. Since all the related costs on distribution, local transportation, distribution/marketing staff salaries are absorbed by the F&V Project, the commission paid to the concessionaries of these outlets is nominal.

(c) While Dhara oil is also being marketed through cooperative stores, it would not be proper to restrict sale of Dhara only through cooperatives and PDS/Super Bazar outlets. The main objective of the NDDB is to make pure oil available to all sections of consumers at reasonable prices. It is therefore proposed to continue marketing Dhara through other retail outlets as well.

(d) Question does not arise.

(e) The Chairman of the NDDB has already been appointed as per the provisions of the Act.

Under utilization of resources of oilseeds production

1150. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the percentage of the under utilisation of the indigenous resources of oilseeds production according to the assessment, if any, made by Government stating the reasons therefor;

(b) to what extent minor and forest origin oilseeds have been tapped stating the estimated collection during 1988-89 and the percentage of oil recovery; and

(c) whether any strategy has been formulated by Government to step up collection of these under tapped oilseeds for larger exploitation of this natural resources; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) Apart from the normal requirements for sowing and direct consumption, the bulk of the oilseeds produced are subjected to oil recovery.

(b) the estimated production during 1988-89 of oil from trees of forest origin is 1.5 lakh tonnes. The average percentage of recovery ranges from 12.5 per cent in the case of sal to 35 per cent in the case of mahua.

(c) The Ministry of Welfare has been entrusted with task of increasing the collection of sal seeds through TRIFED which was declared the Central Nodal Agency in 1988 for collection, processing and development of oilseeds of tree and forest origin. Excise duty rebates are given for use of minor oils which include oils of tree and forest origin.

औद्योगिक संबंध विधेयक तैयार किया जाना

1151. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक संबंधों के बारे में विद्यमान कानूनों को युक्तिसंगत बनाने में कौन-कौन सी मुख्य बाधाएं सामने आई हैं ;

(ख) क्या इस कार्य को पूरा करने और संसद में विधान लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) व्यवसाय संघ और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988 राज्य सभा में 13 मई, 1988 को पेश किया गया था । विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोजक संगठनों तथा अन्यों से

इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का जोरदार विरोध किया । भारतीय श्रम सम्मेलन ने अप्रैल, 1990 में इस मामले पर विचार-विमर्श किया और यह सिफ़ारिश की कि उपरोक्त विधेयक वापस ले लिया जाए और नए औद्योगिक संबंध कानून के लिए विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की जाए, जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों । तदनुसार, यह विधेयक 30 मई, 1990 को वापिस ले लिया गया तथा 8 मई, 1990 को एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई थी । सरकार इस मामले में उन सिफ़ारिशों को, जो समिति द्वारा की जाएंगी ध्यान में रखते हुए अपना दृष्टिकोण बनाएंगी । इस अवस्था पर यह बताना संभव नहीं है कि इस संबंध में कानून के लिए प्रस्ताव संसद के समक्ष कब प्रस्तुत किया जाएगा ।

महिलाओं से संबंधित कानूनों को लागू करने वाले तंत्र को सुदृढ़ किया जाना

1152. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों को लागू करने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) महिला श्रमिकों और बाल श्रमिकों से संबंधित प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राज्यों में प्रायोगिक आधार पर योजना शुरु की गई है। इस योजना में 50% केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है जबकि शेष व्यय को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को भी संशोधित किया गया था ताकि कुछ चुने हुए स्वैच्छिक संगठन अधिनियम के उल्लंघन के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकें।

अधिकांश मामलों में, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं । केन्द्रीय सरकार महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है ।

मानव आवास प्रबंध संस्थान की स्थापना

1153. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगर विकास निगम ने हाल ही में अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से मानव आवास प्रबंध संस्थान की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संस्थान की स्थापना का क्या उद्देश्य है; और

(ग) यह संस्थान किस सीमा तक आवास सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सफल हो सकेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) हुडको द्वारा मानव बस्ती प्रबंध संस्थान (एच० एस० एम० आई०) की स्थापना 1985 में की गई थी । इन्डो-डच करार के अंतर्गत भारतीय मानव बस्ती कार्यक्रम आवास अध्ययन संस्थान रोटरडम के सहयोग से मानव बस्ती प्रबंध संस्थान को सौंपा गया है । मानव बस्ती प्रबंध संस्थान की